कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष 61 अंक 5 मुम्बई अप्रैल- 2017

भारत एक ऐसी भूमि है
जहां हम लक्ष्मी, दुर्गा, आदि शक्ति
और सरस्वती देवी की पूजा करते हैं,
जो हमारे लिए शक्ति के स्रोत रहे हैं।

- श्री कलराज मिश्र

(आयोग मुख्यालय में महिला दिवस पर संबोधन)

केंद्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल रिमोट के साथ
'खादी-एसी जैकेट' का लोकार्पण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष-61 अंक-5 मुम्बई अप्रैल 2017

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष

श्रीमती अन्शु सिन्हा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे
कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्सः 022-26719465
ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईटः www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 28

प्रधान मंत्री ने लिज्जत को महिला विकास पुरस्कार-2016-17 से सम्मानित किया.....
यह एक महिला होने का आनंद है और एक महिला-प्रेम, दायित्व और करुणा की प्रतीक है- श्री कलराज मिश्र .....
शक्ति– राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मलेन -2017 आयोजित....
केंद्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा क्लाइमेट कंट्रोल रिमोट के साथ 'खादी-एसी जैकेट' का लोकार्पण.....
महिला दिवस पर आयोग की मु.का.अ. द्वारा पहली.....
आयोग के अध्यक्ष द्वारा कुरुक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग .....
राज्य कार्यालय, अम्बाला को मिला आई.एस.ओ. .....
सफलता के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन .....
आयोग द्वारा अटोस इंडिया के माध्यम ई-गवर्नेंस की शुरुआत...
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजरात खादी संस्थाओं द्वारा सन्मान कार्यक्रम का आयोजन.....
पंडित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन आयोजित.....
आयोग मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण दिवस .....
आयोग के कर्मचारी आवास, भांडुप में अंतर्राष्ट्रीय महिला .....
खादी बिक्री केंद्रों में शीघ्र ही बिकेंगे जेल कैदियों द्वारा .....
आयोग को रेमंड लिमिटेड से 98000 मीटर खादी कपड़े की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ.....
जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति की 60वीं बैठक .....
पोर्ट ब्लेयर में पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत उद्यमिता .....
आयोग, मुख्यालय, मुंबई में हिन्दी कार्यशाला आयोजित.....
जगत सिंह, शहीद चन्द्रशेखर आजाद अवार्ड-2017 से सम्मानित.....

लेख:चंपारण:महात्मा का उदय.....29 से 33

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....29 से 33

प्रधान मंत्री ने लिज्जत को महिला विकास पुरस्कार-2016-17 से सम्मानित किया

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च 2017 को लिज्जत पापड़ के नाम से लोकप्रिय 'श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़' संस्था को महिला विकास पुरस्कार-2016-17 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार गांधीनगर, गुजरात में भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ शक्ति 2017 के एक पुरस्कार समारोह में 'लिज्जत पापड़' संस्था की अध्यक्षा श्रीमती स्वाती पराड़कर द्वारा प्राप्त किया गया। 'लिज्जत पापड़' एक भारतीय महिलाओं की सहकारी संस्था है जो तेजी से बढ़ते विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में शामिल है। संगठन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है।

महिला दिवस समारोह

यह एक महिला होने का आनंद है और एक महिला-प्रेम, दायित्व और करुणा की प्रतीक है- श्री कलराज मिश्र

"यह एक महिला बनने का आनंद है।" महिला- प्रेम, दायित्व, करुणामयी है, जिसने अपने परिवार को बनाए रखने और प्रियजनों को प्रसन्नचित रखने के लिए सभी कठिनाइयों को खुले दिल से स्वीकार किया।

अभी हम जिस स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वह बहुत सी महान स्त्री शक्तियों द्वारा किये गए बेहतर कार्यों का परिणाम है, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया और स्वयं को समर्पित किया।

भारत एक ऐसी भूमि है जहां हम लक्ष्मी, दुर्गा, आदि शक्ति और सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, जो हमारे लिए शक्ति के स्रोत रहे हैं। भारत की महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वे अगले कुछ वर्षों में हमारे विकासशील देश को एक विकसित देश में बदल देगी।

"घर में और कार्य स्थलों में लिंग भेद पर रोक लगाने और संतुलित विकास के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है," यह बात केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आयोग के केन्द्रीय कार्यालय में दि. 8 मार्च 2017 को संपन्न महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस अवसर पर आयोग में कार्यरत सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि खादी पहले से ही महिला उन्मुख क्षेत्र हैं और यहाँ पर 80-90%

कारीगर महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर उन्होंने, खा.ग्रा.आ. के सभी विभागीय बिक्री केन्द्रों में एक सप्ताह तक महिलाओं को विशेष तौर पर 5% अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की।

इस अवसर पर आयोग के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मंत्री जी ने संबोधित करते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सू.ल.म.उ. मंत्रालय का प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक प्रमुख साधन है। इस वर्ष योजना के तहत 54,345 सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके 4,34,760 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गए हैं। उन्होंने रोजगार प्रदान करने और युवको को सहयोग देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग एंव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधम मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदमों के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाला । उन्होंने आगे बताया कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 'मन की बात' में सभी देशवासियों से खादी की एक वस्तु खरीदने के आह्वान से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की खरीदी में लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला है।

श्री कलराज मिश्र ने इस अवसर पर सूचित किया कि खादी कारीगरों की परिश्रमिक स्थिति को बेहतर और सुदृढ़ बनाना ही खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभी हाल में आयोजित बैठक में कत्तिनों की मजदूरी को प्रति गुंडी (हैंक) 5.50 रूपये से बढाकर 7.00 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है । इससे खादी कत्तिनों को प्रति दिन (08 घंटे के लिए) करीब 200 रूपये परिश्रमिक के तौर पर प्राप्त होंगे। इससे कताई मजदूरी न्यूनतम मजदूरी के सामान हो जाएगी और खादी क्षेत्र से कारीगरों के पलायन को रोका जा सकेगा।

स्फूर्ति कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करते हुए, उन्होंने बताया कि इस क्लस्टर कार्यक्रम के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन में 40% की वृद्धि होगी। खादी और ग्रामोद्योगों के उपार्जन में, खादी में 60% और ग्रामोद्योगों में 50% की वृद्धि की उम्मीद है। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार, खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र के बारे में बहुत गंभीर है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान कर सकता है, जिससे खादी में न्यूनतम 13500/- रु. पूंजी निवेश में और इसी तरह ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत न्यूनतम एक लाख पूंजी निवेश तक रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इस अवसर पर आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी / वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री मोहित जैन, सयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सतपाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस. राव और श्री वाय. के. बारामतिकर उपस्थित थे।

एसएमई महिला दिवस समारोह

इंडिया एसएमई फोरम की महिला शाखा द्वारा शक्ति- राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मलेन -2017 आयोजित

सम्पूर्ण देश में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनमें उद्यमिता की भावना पैदा व पोषित करने में उनकी इच्छा को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से, महिला उद्यमी मंच द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक नया प्रतिमान तैयार करने और ब्रांडों का निर्माण करने एवं व्यापार में महिलाओं के लिए अवसरों पर विचार-विमर्श करने और महिला उद्यमियों को सहयोग देने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ भारत की बड़ी तेजी से उभरती 9 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया एवं स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत महिला उद्यमियों का चयन करने के लिए अनुमोदन पत्र जारी किए गए।

इस अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से इंडिया एसएमई फोरम द्वारा आयोजित "शक्ति – राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मलेन -2017" की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर श्री कलराज मिश्र ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलायें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे आकार लेगी, उसमें महिलायें महत्वपूर्ण हितधारक हैं। यह दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के नाम से जाना जाता है - उनकी शक्ति, उपलब्धियां और उनकी सफलता की कहानी के लिए। 'भारत की महिलाएं अपने विकासशील देश को आने वाले वर्षों में एक विकसित देश में बदल देगी'।

कार्यशाला में प्रमुख वक्ताओं में, मुख्य अतिथि श्री कलराज मिश्र अलावा केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, राष्ट्रीय बैंकिंग, भारतीय स्टेट बैंक के एमडी श्री राजनीश कुमार, ऐड गुरु और इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष श्री प्रहलाद ककड़, उद्यम निवेशक और इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, सह संस्थापक और डीजी इंडिया एसएमई फोरम सुश्री सुष्मा मोर्थनिया और जीएम- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उधम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई श्रीमती उमा शंमुखी सिस्टला, शामिल थे।

कार्यशाला में सभी स्टार्टअप और विद्यमान महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को भाग लेने और सलाहकारों, बैंकरों और सफल उद्यमियों के अलावा इच्छुक उद्यमियों के साथ एक नेटवर्क तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

केंद्रीय एम.एस.एम.ई. राज्यमंत्री द्वारा
क्लाइमेट कंट्रोल रिमोट के साथ 'खादी-एसी जैकेट' का लोकार्पण

पटना, 8 मार्च, 2017 : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बिहार के नवादा में अपने निर्वाचन क्षेत्र खानवां में 'खादी एसी जैकेट' नामक एक विशेष जैकेट का शुभारंभ किया।

यह ख़ास जैकेट किसी भी समय एक कूल रहती है क्योंकि स्वयं-कूलिंग लिनन जैकेट कपड़े में दो विकल्प प्रदान करती है - गर्मी के लिए लाल बटन और कूलिंग करने के लिए हरा बटन।

इससे तापमान अंतर 20 डिग्री हो सकता है, ऐसा कहते हैं जो जैकेट के विकास और डिजाइन में शामिल हैं।

श्री सिंह ने कहा "यह आपको किसी भी समय ठंडा रखती है, यह सिर्फ एक आकर्षक की चीज नहीं है।" उन्होंने कहा कि खानवां (नवादा) की कत्तिन महिलाओं के लिए यह बहुत गौरव और हर्ष का विषय है, जब वे खादी एसी जैकेट के लोकार्पण समारोह की गवाह बनी हैं।

मंत्री महोदय ने संवाददाताओं से कहा, "यह खानवा के कपास और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है।"

जैकेट में, कथित तौर पर, ठंडे और गर्म हवा के फैन लगाए गए हैं, जो बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। एक एमआईटी स्नातक ने इस "जलवायु गियर" तकनीक को विकसित करने में मदद की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के छात्र पहनने के लिए अपने स्वयं की एसी के डिजाइन के साथ मदद के लिए आगे आये हैं।

श्री सिंह ने कहा कि फ्रंटलाइन पर सैनिकों के लिए यह जैकेट एक वरदान साबित होगी। "सियाचिन में इसके लाभों की कल्पना की जाय, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धक्षेत्र है, जहां तापमान शून्य से नीचे 50 डिग्री हो सकता है।"

"एसी जैकेट" बाजार में जल्द ही प्रवेश करेगी, जिसका औसतन मूल्य एक हाफ जैकेट के लिए 18,000 रुपये से लेकर और एक पूर्ण बाजू वाली के लिए 25,000 रुपये होगा।

श्री सिंह ने यह भी कहा कि नवादा शहर, सौर ऊर्जा वाले खादी के जलवायु नियंत्रण जैकेट एवं मशरूम खेती के लिए नई सफलता की कहानी लिख रहा है। "हम और बैंक इस विशेष प्रयोजन का समर्थन करते हैं।"

☆☆

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने सौर चरखा मॉडल के विस्तार हेतु नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उनकी टीम के साथ एक बैठक की।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह के अध्यक्षता में 31 मार्च 2017 को ऐजावल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एमएसएमई-डीआई, एनएसआईसी, वाणिज्य और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने, हनम छांतू, ऐजावल स्थित बेंत और बांस स्फूर्ति क्लस्टर का भी अवलोकन किया।

महिला दिवस पर आयोग की मु.का.अ. द्वारा पहली विदेशी महिला ग्राहक को सम्मान

"अंतराष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर शोरूम का संचालन एवं बिक्री पूर्णतया महिला कर्मचारियों/अधिका-रियों के द्वारा किया गया।

इस मौके पर श्रीमती अंशु सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी लाउंज की महिला कार्यकर्ता एवं प्रथम विदेशी

महिला ग्राहक को फूल एवं खादी रुमाल देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग नई दिल्ली की सभी महिला कर्मचारियों एवं महिला अधिकारीयों को भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ० क्षेत्र श्री सत्यनारायण शुक्ल और प्रबन्धक खादी इंडिया श्री ए.के. गर्ग भी उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा कुरुक्षेत्र में खादी ग्रामोद्योगी गतिविधियों का निरीक्षण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि खादी-आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहें हैं।

उन्होंने गांधीजी की दूरदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए कहा, गांधीजी जानते थे कि आत्मनिर्भरता केवल खादी के कताई और बुनाई से ही संभव है। उन्होंने आगे कहा कि गांधीजी के अनुसार कताई चरखा आत्म-सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक निर्भरता का प्रतीक है। उस समय, गांधीजी के हितैषी चरखा ने एक सामाजिक और राजनीतिक पहचान हासिल की जो जनता के बीच रोजगार और आत्म-सम्मान पैदा करने में सक्षम था। इसके पास गांव से पलायन रोकने की शक्ति थी|

उन्होंने कहा, हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री मोदी ने चरखा की इसी शक्ति को स्वीकार किया और लोगों से ग्रामीणों कारीगरों की मदद के लिए खादी को उपयोग में लाकर खादी को बढ़ावा देने की अपील की। श्री सक्सेना ने वर्तमान सरकार द्वारा चरखा के विकास और सुधार हेतु किये गए प्रयासों पर भी प्रकाश डाला| आयोग के अध्यक्ष ने कारीगरों को समय पर पूरे वेतन का भुगतान करने की भी अपील की। अध्यक्ष महोदय ने खादी-विचार वस्त्र के डिजाइन, ब्रांड और खादी की छवि निर्माण और कारीगरों के मजदूरी के प्रत्यक्ष बैंक स्थानांतरण, कारीगरों के मजदूरी में वृद्धि आदि जैसे क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गए प्रयासों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की|

अध्यक्ष महोदय ने संस्थाओं से आग्रह किया कि उन्हें समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर बैठकें कर विचार-विमर्श करना चाहिए जिससे प्रगति के मार्ग खुल

सके।

उन्होंने, 8 मार्च 2017 को महाराणा प्रताप चौक पर निर्मल खादी ग्रामोद्योग समिति के खादी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया।

महिला दिवस पर उन्होंने खादी इंडिया बिक्री केंद्र में कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं।

अध्यक्ष महोदय ने कुरुक्षेत्र के शिवशक्ति हस्तनिर्मित पेपर इकाई का भी निरिक्षण किया, उन्होंने वहां पर इकाई के प्रबंधक श्री राकेश गोयल और श्री खेमचंद गोयल के साथ बातचीत की, जिन्होंने उन्हें हस्तनिर्मित उत्पादों के कच्चे माल और निर्माण लागत के बाज़ार मूल्य के बारे में जानकारी दी। उद्यमियों ने विपणन सहायता के लिए अध्यक्ष से आग्रह किया।

श्री सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग संघ, नेरड में केआरडीपी के तहत स्थापित सामान्य सुविधा केन्द्रों का निरिक्षण किया।

इस अवसर पर उन्होंने संस्था के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया।

राज्य कार्यालय, अम्बाला को मिला आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाण पत्र

आयोग के राज्य कार्यालय, अम्बाला को आई.एस.ओ.9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह प्रमाण पत्र टी.यू.वी. इंडिया प्रा. लि., मुंबई द्वारा जारी किया गया।

श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर-कमलों द्वारा यह प्रमाण पत्र दिनांक 08 मार्च, 2017 को कुरूक्षेत्र में आयोजित हरियाणा प्रदेश की सभी खादी संस्थाओं की बैठक में श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक को हस्तगत किया गया। इस अवसर श्री सक्सेना कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि हरियाणा राज्य कार्यालय को यह उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है।

उन्होंने, राज्य निदेशक की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य में खादी का कार्य प्रगति पर है। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि इसी प्रकार अन्य राज्य निदेशक भी कार्य करें ताकि खादी कार्य को बढ़ावा मिल सके, साथ ही खादी संस्थाओं को भी चाहिए कि वह भी आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रयास करें।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 18, मार्च 2017 को कोयम्बटूर में आधुनिक खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। इसी तरह के कई आउटलेट पूरे देश में खोले जाने हैं।

सफलता के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन कठिन परिश्रम, कार्य संचालन और जुनून से ही सफलता पाना संभव है

-विनय कुमार सक्सेना

हाँ, यह एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन कार्य के प्रति समर्पण भावना और एक टीम वर्क ने इसे संभव बनाया है- यह बात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 1250/- करोड़ रूपये के लक्ष्यांक की उपलब्धि हासिल करने पर केंद्रीय कार्यालय के ढेबरभाई कक्ष में आयोजित एक बैठक में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और सूचना और प्रौद्योगिकी निदेशालय के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और सूचना और प्रौद्योगिकी निदेशालय के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के प्रयासों की सरहाना करते हुए कहा कि आपके कड़े प्रयासों से ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने आग्रह किया कि आयोग को नंबर एक संगठन बनाने के लिए, अन्य निदेशालयों को भी इसी तरह से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शीघ्र निर्णय लेने और प्रक्रिया को छोटा करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, 'सभी प्रबल और सक्षम हैं खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र काम करने के लिए वृहद एवं विशाल है।

मधुमक्खी पालन और चर्म जैसे उद्योगों में काफी संभावनाएं हैं। इन पर एक मिशन को लेकर काम करने की जरूरत है।'

आयोग के वित्तीय सलाहकार सुश्री उषा सुरेश ने इस अवसर पर अपने संबोधन में टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इच्छा शक्ति, समर्थन और मार्गनिर्देशन के माध्यम से कोई भी कार्य करना संभव है । यह अपेक्षाओं से बहुत अधिक है और उन्हें वितरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, वर्ष 2017-18 में बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्यपाल ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा

कि 2017-18 का लक्ष्य बड़ा और अधिक होना चाहिए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस. राव ने पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि, पूरी टीम ने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दिन-रात कठिन परिश्रम किया है| उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग पहली बार 'एक एकल योजना' के माध्यम से 1250 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा, "अधिकारी विश्वसनीयता, प्रेरणा और सम्मान के लिए तत्पर रहे तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है"। पीएमईजीपी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपने अनुभव बांटते हुए बताया कि इसमें, संपूर्ण व्यवस्था कैसे काम करती है, शुरुआत में आने वाली छोटी-छोटी परेशानियां, इन्हें कैसे निपटाया गया, इन सभी अवयवों में डिजिटलाइजेशन, अधिकतम उपयोग करने के लिए एक बेहतर मशीनरी, सत्यापन की प्रक्रिया, कारपोरेशन बैंक इत्यादि की भूमिका शामिल है।

इस अवसर पर आयोग के प्रौद्योगिकी निदेशालय के निदेशक श्री एम. राजन बाबू ने बताया कि पोर्टल कैसे प्रारंभ किया गया और इसे सफलतापूर्वक कैसे आगे बढ़ाया गया। उन्होंने संक्षिप्त में यह भी बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा पोर्टल में एक माह की अवधि के भीतर शून्य निवेश एंव विशेष सुविधाओं के साथ इस पोर्टल को विकसित किया गया था, इससे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बहुत बड़ी धन राशि की बचत हुई है|

पूर्व में, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के निदेशक श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर ने बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय और सूचना और प्रौधोगिकी निदेशालय द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबी और कठिन कार्यप्रणाली पर प्रयास किये गए।

उन्होंने उन सभी की सराहना की जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस कार्य को अंजाम दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यदि हम सामूहिक रूप (टीम में) में कार्य करते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं|

आयोग द्वारा अटोस इंडिया के माध्यम ई-गवर्नेंस की शुरुआत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने कार्यों में पारदर्शिता तथा योजनाबध्द दक्षता लाने हेतु अटोस इंडिया के माध्यम से ई-गवर्नेंस की शुरुआत कर रहा है, जो अपनी तकनीकी के माध्यम से बिजनेस संबधित समस्याओं का समाधान करने की एक प्रतिष्ठित कंपनी है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री वी.के. सक्सेना ने अपने केंद्रीय कार्यालय में प्रोजेक्ट की शुरुआत करते समय कहा कि यह प्रक्रिया, अटोस इंडिया की भागीदारी के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और डिजिटाइजेशन का उन्नयन करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे सम्पूर्ण भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग में एक नए युग की शुरूआत होगी । उन्होंने आगे कहा कि यह

पहली बार होगा कि यह डिजिटाइजेशन कार्य की यह व्यवस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सभी कार्यालयों, बिक्री केन्द्रों, पूनी संयत्रों, उत्पादन केन्द्रों इत्यादि में एकीकृत रूप से की जा रही है, डिजिटल इंडिया जोकि प्रधान मंत्री का विजन है | इस ई-गवर्नेंस व्यवस्था की संरचना- योजना बनाने, बजट बनाने, प्रापण, व्यय प्रबंधन करने, उत्पादन करने और खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री आदि क्षेत्रों से सम्बंधित कार्यों में तीव्रता लाने हेतु तैयार की गयी है|

अटोस का चयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था| एटोस एक प्रतिष्ठित फर्म है, इस कंपनी ने कई उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियों जैसे

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वोडाफोन, आइडिया, और यहां तक कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में ओलंपिक के समृद्ध और विविध अनुभव है, ऐसे कंपनियों का आईटी सम्बंधित समस्याओं का समाधान किया|

इस ई- गवर्नेंस प्रोजेक्ट को, खादी सुधार विकास कार्यक्रम (के.आर.डी.पी.) के तहत निधियन किया गया है और इसका कार्यान्वयन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय सहित इसके छः केंद्रीय पूनी सयंत्रों, 44 राज्य तथा मंडलीय कार्यालयों, सभी बिक्री केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, आदि की सभी वित्तीय गतिविधियों को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में किया जायेगा | इस परियोजना को पूरा करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस कार्य को नौ महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केंद्रीय कार्यालय में अटोस के कर्मचारियों को कार्य करने के लिए सहयोग और सहायता करेगा|अटोस खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा|

श्री शिरीष फडके, कंट्री हेड, बिज़नस ऑपरेशन, अटोस इंडिया ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केवीआईसी प्रोजेक्ट उनके लिए एक प्रतिष्ठित कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना यह एक नेक काम है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया है|

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजरात खादी संस्थाओं द्वारा सन्मान कार्यक्रम का आयोजन

गुजरात ग्रामोद्योग संस्था संघ के तत्त्वाधान में भारत सरकार और गुजरात सरकार के प्रयासों को सम्मानित करने हेतु गुजरात की संस्थाओं द्वारा एक सम्मान समारोह कार्यक्रम- गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में दिनांक 19.03.2017 को आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग मिशन टू चैंपियन खादी के तहत स्कूल-प्रशासन और कर्मचारियों को हर मंगलवार को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर समारोह में गुजरात सरकार के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुडासामा, आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार देसाई, नडियाड खादी संस्था के अध्यक्ष श्री लाल सिंह वाडोदिया, गुजरात विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री राजेंद्र खिमदिजी, संस्था संघ के अध्यक्ष श्री अभय सिंह पटेल और कत्तिन और बुनकर संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर गणमान्य लोगों ने गुजरात सरकार के खादी को बढ़ावा देने की दिशा में किये गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि चरखा का इतिहास अब पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

आयोग के अध्यक्ष महोदय ने खादी आंदोलन को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने, 2016 में प्रधान मंत्री के पहली मन की बात को दोहराते हुए कहा, "खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन,"-इस कथन में करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की क्षमता है।

पंडित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट में अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन आयोजित

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिनांक 16-17 मार्च 2017 को आयोग के विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों एंव गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के अखिल भारतीय प्राचार्य सम्मेलन का उद्घाटन आयोग के एक गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र, पंडित दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, चित्रकूट, जिला-सतना, मध्यप्रदेश में किया। इस सम्मलेन का आयोजन आयोग के क्षमता विकास निदेशालय द्वारा किया गया।

इस प्रमुख सम्मलेन में सचिव, डी.आर.आई., आयोग के सदस्य (मध्य क्षेत्र), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मध्य क्षेत्र), अध्यक्ष महोदय के सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.बी.) भी उपस्थित थे।

अपने स्वागत भाषण में श्री एम.बी. काम्बले, निदेशक(दक्षता विकास) ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रशिक्षण की नीति में बहुत बदलाव हुए हैं, विशेष रूप से गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के लिए छात्रवृत्ति समाप्त करने और वेतन सहयोग, जिससे नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्यांक प्रभावित हुए हैं। इसलिए उपयुक्त संशोधनों के लिए नीतियों में छूट की आवश्यकता है। सभी प्राचार्यों ने आत्म-परिचय के दौरान अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया।

आयोग के सदस्य (मध्य क्षेत्र) श्री तोमर ने प्रतिस्पर्धात्मक माहौल के तहत गुणवतायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया ताकि अधिक रोजगार योग्यता

के लिए नौकरी प्रदाताओं द्वारा प्रमाण पत्र की पहचान हो सके।| प्रशिक्षण केंद्रों को अपने उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की स्थिति जानने के लिए नियमित रूप से जानकारी रखनी चाहिए| सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को स्व-स्थायी मोड पर चलने का प्रयास करना चाहिए, सरकारी वित्तपोषण केवल उत्प्रेरक है और इसीलिए सरकारी समर्थन की निरंतरता कायम रखने पर जोर न दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में प्रशिक्षण केंद्रों की गतिविधियों और प्रगति के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया और प्राचार्यों से आग्रह किया कि वे प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवीनता, वचनबद्धता और समर्पण भाव के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करें । वर्तमान में किए जाने वाले स्टीरियो प्रकार की गतिविधियों के बजाय केंद्र की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए अपनी सोच, रवैया और कार्य-संस्कृति में बदलाव लाए।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम- उपलब्ध स्थानीय संसाधनों, उत्पादों के बाज़ार मांग, रोजगार की संभाव्यता; क्षेत्र के विशेष कौशल व्यवस्था पर इत्यादि में आधारित होना चाहिए, प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए ताकि प्रशिक्षण अंततः रोजगार के अंतिम लक्ष्य के साथ पूर्ण हो सके। खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने आदि जैसे स्टीरियोटाइप पाठ्यक्रम निराशा पैदा करते है जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजित किये जाते है| इसलिए गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिए जिससे खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृध्दि हो सके|

उन्होंने आगे कहा कि प्रशिक्षण केंद्र में पर्याप्त भूमि, इमारतों और मशीनें हैं, जो कई वर्षों से बेकार पड़े हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों को अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग, उपयुक्त संसाधनों का निर्माण करने के लिए उत्पादक तरीके से, और उन अप्रयुक्त मशीनरी को सूचीबद्ध करना चाहिए ताकि उत्पादक उपयोग के लिए अन्य केंद्रों को इसे दिया जा सके।

प्रशिक्षण केंद्र इस उद्देश के साथ प्रशिक्षण प्रदान करें जिससे प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्वयं का या उपार्जनपरक रोजगार प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण देने के बाद केंद्र की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों के रोजगार की योग्यता का मूल्यांकन न केवल प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को मापता है बल्कि यह रोजगार की अधिक संभावना वाले स्रोतों के आयोजन के लिए भी उपयोगी है। पूर्व में प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण केंद्रों में नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए।

प्रशिक्षण केंद्रों को एक नियोजित और उचित तरीके से संसाधनों का उपयोग करके स्वयं स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। बजटीय संसाधनों के तहत प्रदान की जा रही सहायता केन्द्रों को केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना है, यह सहायता हमेशा के लिए जारी नहीं रखी जा सकती। केन्द्रों को अपने स्वयं के पैरों पर खड़े

होने की दिशा में धीरे-धीरे प्रयास करना होगा।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री की मधु (स्वीट) क्रांति को, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करके मधुमक्खीपालन को स्व-रोजगार के रूप में रोजगार प्रदान करके, सफल बनाया जा सकता है। इससे न केवल स्थायी रोजगार प्राप्त होगा, बल्कि शहद के उत्पादन में भी वृद्धि होगी और देश में मधु क्रांति आएगी | प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण हेतु 100 या इससे अधिक संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक केंद्र में 500 मधुमक्खी पेटियां संवितरित किये जाये, इस प्रकार से सभी केंद्रों में 16000 मधुमक्खी बक्से, 11.60 लाख कि.ग्रा. शहद का उत्पादन कर सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्रों को मधु क्रांति की सफलता के लिए प्रयास करने का अवसर मिला है।

माननीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर सभी गैर-विभागीय केंद्रों की समस्याओं की बात सुनी । उनमें से ज्यादातर केन्द्रों ने बताया कि वेतन सहयोग और उम्मीदवारों के लिए छात्रवृति बंद करने से केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं आते हैं क्योंकि अन्य सरकारी विभाग अपने उम्मीदवारों को इस प्रकार की सुविधा देते हैं| आयोग के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि उपयुक्त समाधान के लिए एनडीटीसी के मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

सभी प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श सत्र के दौरान यह देखा गया है कि अधिकांश केंद्र नियमित प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहें हैं और छात्रवृति सम्बंधित सुविधा समाप्त करने से, नियमित पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है|

यह भी पाया गया कि पीटीए पद्धति के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सहायता से संचालित पाठ्यक्रम, पीटीए पद्धति (पेटर्न) को समाप्त करने से उपरोक्त पाठ्यक्रम नहीं चलाए जा सकते हैं। पीटीए पैटर्न प्रशिक्षण केंद्रों के लिए आवश्यक आधार पाठ्यक्रमों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के संचालन में उपयोगी थे, ताकि केंद्र को ज्यादा आईआरजी कमाने के रूप में उपयोग किया जा सके।

यह भी सूचित किया गया कि स्थानीय प्रशिक्षकों का वेतन पर्याप्त नहीं है इसमें वृद्धि किया जाना अपेक्षित है चूंकि एल.एस.टी. पद्धति के तहत न्यूनतम वेतन होने से प्रशिक्षक अधिकतर मामलों में इस कार्य के लिए तैयार नहीं होते हैं|

पाठ्यक्रमों ने एनएसक्यूएफ अनुपालन का किया है जिसके लिए प्रशिक्षण केंद्रों को सीबी के निदेशालय में योग्यता सम्बधित फाइलें प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रशिक्षण केन्द्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उपयोग में लाने की योजना और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीकरण करने का प्रस्ताव रखना चाहिए । इसी तरह, रखी हुई निष्क्रिय मशीनों की सूची तैयार करनी चाहिए, इन मशीनों को निष्क्रिय रखे जाने के कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इन मशीनों को प्रभावी उपयोग में लाने के सम्बन्ध में आगे की योजना के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए|

प्रशिक्षण केंद्रों को सरकारी एजेंसियों और सीएसआर कार्यालय के साथ सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उनके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

आयोग मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण दिवस का आयोजन

विश्व में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धि के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर आयोग मुख्यालय के प्रार्थना हॉल में महिला सशक्तिकरण अनुभाग ने, जीवन विद्या मिशन से श्रीमती सुनीता नारा को आमंत्रित करके एक प्रेरणात्मक व्याख्यान का आयोजन किया, इस व्याख्यान में उन्होंने 'तनाव मुक्त होकर और सुखी जीवन कैसे बनाया जाए' इस विषय पर जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण कक्ष की अध्यक्ष श्रीमती बिरला महोर, सदस्य श्रीमती गीतांजली राधाकृष्णन, सदस्य श्रीमती नीलीमा सालुंखे और सदस्य श्रीमती ज्योति भट्ट उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम का प्रारंभ श्रीमती गीतांजली राधाकृष्णन द्वारा किया गया श्रीमती गीतांजली

(शेष पृष्ठ 18 पर)

आयोग के कर्मचारी आवास, भांडुप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन

वे सक्षम, बहुमुखी और सफल है - कार्यस्थल पर गतिशील और घर को अपार स्नेह देने वाली हैं। वो एक ऐसा सूत्र है जो जीवन के हर खंड को आपस में बंधे रखती हैं। महिलाएं हमारे मन और समाज में जो स्थान रखती है उसके सामने कोई भी सम्मान कम है।

जैसा कि महिलाऐं समाज का प्रमुख हिस्सा है और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समाज में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदानों पर ध्यान केंद्रित करने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को पूरे हर्सौल्लास के साथ दुनिया के सभी देशों में भिन्न- भिन्न रूप से मनाया जाता है। इसी क्रम में महिला

समाज को उनके बहुमूल्य योगदानो के लिए सम्मानित करने और उनकी सराहना करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी आवास, खादी दर्शन सोसाइटी, भांडुप में 11 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोज पूर्ण उत्साह के साथ किया गया।

इस मौके के मुख्य अतिथि एवं योग विशेषज्ञ, श्रीमती सुधा मालोडे ने इस अवसर पर 'महिलाओं के लिए योग के लाभ' पर व्याख्यान दिया और समझाया कि किस प्रकार योग की सहायता से महिलाएं पूरी प्रवीणता और शांति के साथ अपनी अनेकों जिम्मेदारियों को संभाल सकती हैं। योग न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन बनाये रखता है। ☆☆

खादी बिक्री केंद्रों में शीघ्र ही बिकेंगे जेल कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद

नई दिल्ली, 2 मार्च 2017: तिहाड जेल और अन्य जेलों के कैदियों द्वारा बनाये गए उत्पादों की बिक्री पूरे देश में स्थित खादी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से शीघ्र ही की जाएगी।

"हमें विश्वास है कि जेलों में बने उत्पादों के लिए एक बिक्री मंच प्रदान करने से उनका व्यक्तिगत रूप में परिवर्तन होगा और उनका सामाजिक समावेश होगा।

आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि "हम गुड़गाँव जेल और तिहाड जेल के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री, बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कर रहें हैं। आगे हम अन्य जेलों के कैदियों द्वारा बनायी गयी वस्तुओं की भी बिक्री करेंगे।"

इन उत्पादों में रेडीमेड वस्त्र, हैंडलूम, फर्निचर, कम्बल, स्टेशनरी इत्यादि शामिल हैं। यह निर्णय साबरमति आश्रम, अहमदाबाद में 27 फरवरी को आयोजित आयोग की बैठक में लिया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कत्तिनों के वेतन में वृद्धि करने और स्वदेशी कपड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मृत खादी संस्थानों को पुनर्जीवित करने का भी निर्णय लिया।

जो संस्थायें उक्त निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं वहां पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सभी संस्थाओं के माध्यम से सामान रूप से मजदूरी में बढ़ोतरी करने पर जोर देगा और एमडीए (विपणन विकाससहायता) को रोकने की सिफारिश करेगा।

श्री सक्सेना ने कहा कि आयोग ने खादी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और राज्य निदेशालयों में शामिल व्यक्तियों को उनके पुनरुद्धार करने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अब देश में खादी उत्पादन को तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है, चूँकि प्रधान मंत्री जी के विजन के आधार पर दो वर्षों में उत्पादन को वर्तमान स्तर 1065 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5000 करोड़ रूपए करने की जरुरत है।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि "राज्य निदेशालयों के शामिल व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित प्रतिस्पर्धी सफलता के आंकलन पर, आयोग भी वेतन वृद्धि और/अथवा उचित प्रोत्साहनों के अन्य रूपों का भुगतान करने का निर्णय ले सकता है।

(साभार:द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया)

(पृष्ठ से 17 आगे)

आयोग मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण दिवस.....

राधाकृष्णन ने महिलाओं के सम्मान में विश्वस्तर पर मनाया जाने वाला इस दिन के महत्त्व के सबंध में संक्षिप्त रूप में जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात् श्रीमती सुरेश नार ने अपने भाषण से उपस्थित सभी श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक समानता लाने की जरुरत है और पुरुषों को समझने जरुरत है कि महिलाओं की केवल घर और परिवार संभालने की जिम्मेदारी है। इसके बजाय, दोनों (पुरुष और महिला) ही अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों संपन्न करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। उसने बताया कि पुरुषों को भी घर और परिवार के लिए अपनी ज़िम्मेदारी और अन्य सभी कामों को समझने की ज़रूरत है, ताकि महिलाओं को स्वयं के बारे और अपने के कैरियर के बारे में सोचने के लिए कुछ समय मिल सके । महिलाओं को अपनी शक्ति और क्षमताओं की भी पहचान होनी चाहिए और सशक्तिकरण की दुनिया की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के महिला कर्मचारी श्रीमती निशा सोनेकर द्वारा लिखी गई "तरंग कवितासंग्रह" पुस्तक का विमोचन किया गया । उन्होंने इस पुस्तक की कुछ कविताएं भी पढ़कर सुनाई।

तत्पश्चात प्रशासन की उप निदेशक श्रीमती बिरला महोर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम का समापन किया।

आयोग को रेमंड लिमिटेड से 98000 मीटर खादी कपड़े की आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ

25 मार्च 2017, मुंबई: खादी और ग्रामोद्योग आयोग को रेमंड लिमिटेड से 98000 मीटर खादी कपड़े की एक मुश्त आपूर्ति का आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें से 32000 मीटर कपड़े की आपूर्ति 31 मार्च से पहले कर दी जायेगी एवं शेष आपूर्ति मई के अंत तक की जायेगी। यह आर्डर 2 करोड़ रु. से अधिक का है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आपूर्ति आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि, यह किसी भी बड़े कॉरपोरेट कंपनी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा आपूर्ति ऑर्डर है। उन्होंने, खादी वस्त्रों की मार्केटिंग में कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के प्रवेश की शुरुआत को खादी के लिए अच्छा बताते हुए कहा कि इस प्रकार से यह कारीगरों को स्थायी रोजगार और आजीविका के लिए सहयोग प्रदान करेगा।

रेमंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय बहल ने कहा कि केवीआईसी ने 6 दिसंबर, 2016 को रेमंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते के अंतर्गत रेमंड के द्वारा खादी वस्त्र का यह शुरूआती आपूर्ति आर्डर दिया गया है। इससे पूर्व जनवरी और फरवरी माह में रेमंड ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से विविध प्रकार के 6000 मीटर खादी कपड़े परीक्षण व नमूने के रूप में लिए थे।

संयुक्त दौरे के बाद, रेमंड ने गुजरात, राजस्थान और अन्य स्थानों से कपड़े तैयार करने के लिए विभिन्न क्लस्टरों का चयन किया है। केवीआईसी रेमंड को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रे और पूर्ण निर्मित खादी कपड़े की आपूर्ति करेगा। रेमंड खादी वस्त्रों को उच्च फैशन व आधुनिक बाज़ारों के लिए डिज़ाइनर परिधान हेतु डिजाइन इनपुट एवं मूल्यवर्धन उपलब्ध कराएगा।

श्री सक्सेना ने बताया कि खादी कारीगरों के कल्याण पर ही खादी ग्रामोद्योग आयोग का पूरा ध्यान केंद्रित है इसलिए इन क्लस्टरों में कार्यरत खादी कारीगरों को इस तरह की विशेष आपूर्ति के मार्जिन से 5 % अतिरिक्त मजदूरी सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह थोक आदेश खादी कारीगरों के श्रम में 3,92,000 अतिरिक्त मानव श्रम घंटों का निर्माण करेगा।

समझौते के अनुसार रेमंड प्रति वर्ष न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपए मूल्य के वस्त्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग से क्रय करेगा।

जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति की 60वीं बैठक का आयोजन

जिला स्तरीय टास्क फ़ोर्स समिति की 60वीं बैठक 18 जनवरी, 2017 को पोर्ट ब्लेयर में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत दक्षिण अंडमान जिला से प्राप्त ऋण आवेदनों पर कार्यान्वयन करने हेतु पोर्ट ब्लेयर जिला कार्यालय के सहायक आयुक्त डी.ए.एन. आई.सी. एस. श्री महेश कुमार गुप्ता के अध्यक्षता में संपन्न हुई|

बैठक के दौरान उद्योग निदेशक श्री अजीत आन्नद, भारतीय स्टेट बैंक के जिला प्रबंधक श्री पी.के. उम्मेर फारूक, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय बैंक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (सी.आर) श्री मनोज कुमार और अन्य बैंक तथा प्रशासन के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे| डी.एल. टी.एफ. सी. के समक्ष कुल 17 लाभ ग्राहियों के ऋण मामले प्रस्तुत किये गए तथा 43.94 लाख रु.की परियोजना लागत के 17 ऋण आवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्त पर विचार करने हेतु सिफारिश की गई|

पोर्ट ब्लेयर में पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

पोर्ट ब्लेयर में 13 फरवरी 2017 को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत छः दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया|

सैद्धांतिक सत्र के दौरान डॉ.बी.आर. आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्योग निदेशालय, डी.आई.सी., खादी और ग्रामोद्यिग मंडल, जे.एन.आर. एम्., नाबार्ड, बैंक, ए.एन.आई.आई. डी.सी.ओ.,पोलिस और श्रम विभाग के विशेषज्ञ सदस्यो ने स्व-रोजगार उद्यमों को स्थापित करने के विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डाला|

कार्यक्रम के अंतिम दिन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सफल उद्यमियों और प्रशिक्षणार्थियों ने अपने–अपने अनुभव बाँटे|

इस कार्यक्रम में कुल 40-50 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभग्राही उपस्थित थे|

जगत सिंह, शहीद चन्द्रशेखर आजाद अवार्ड-2017 से सम्मानित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालय, अम्बाला छावणी हरियाणा में पदस्थ श्री जगत सिंह, कार्यकारी (ग्रामोद्योग)को अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर सामाजिक कार्यों में सराहनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय का "शहीद चन्द्रशेखर आजाद अवार्ड -2017 " से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हासिल कर श्री जगत सिंह ने आयोग का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रौशन किया है।

अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के वंशज एवं सुपौत्र श्री अमित आजाद द्वारा हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुनिल कुमार गुलाटी, आई.ए.एस. एवं हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश पांचाल की गरिमामयी उपस्थिति में श्री जगत सिंह को यह अवार्ड गत दिवस गुरुग्राम में एक शहीदों के नाम कार्यक्रम में दिया गया। यह कार्यक्रम शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हरियाणा नवनिर्माण सेना एवं करुणा जनकल्याण समिति द्वारा आयोजित किया गया था।

आयोग, मुख्यालय, मुंबई में हिन्दी कार्यशाला आयोजित

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित लक्ष्यांकों को प्राप्त करने के क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुख्यालय, मुंबई के ढेबर भाई सभाकक्ष में दिनांक 21 मार्च, 2017 को दो सत्र में एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला का प्रथम सत्र खादी और ग्रामोद्योग आयोग में कार्यरत प्रचार अधिकारियों (पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ आर्टिस्ट, उप संपादक, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग मेनेजर), प्रचार सहायक-I एवं II (कनिष्ठ उप संपादक, कलाकार, पुस्तकालय सहायक), वरिष्ठ कार्यकारियों (प्रशिक्षण अधिकारियों), कार्यकारियों (सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक), वरिष्ठ कार्यकारियों (अर्थ अन्वेषक) को "हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन" विषय पर एवं द्वितीय सत्र निदेशकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशक-1 को "कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन" विषय पर जानकारी देने हेतु आयोजित किया गया था

कार्यशाला के प्रथम सत्र के शुभारंभ में श्री कृष्ण पाल, सहायक निदेशक/प्रभारी (हिन्दी विभाग) ने अतिथि वक्ता श्री सुखबीर सिंह, हिन्दी अधिकारी (सेवानिवृत्त), खादी और ग्रामोद्योग आयोग का परिचय देते हुए कार्यशाला में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया । श्रीमती ऊषा मिश्रा, प्रचार अधिकारी ने अतिथि वक्ता को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया।

अतिथि वक्ता श्री सुखबीर सिंह, हिन्दी अधिकारी (सेवा निवृत्त) ने हिन्दी टिप्पण के बारे में बताते हुए सरकारी कामकाज में सरल हिन्दी के प्रयोग पर ज़ोर दिया। श्री सुखबीर सिंह ने उपस्थित कर्मचारियों से हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन का भी अभ्यास कराया। अंत में श्री कृष्ण पाल, सहायक निदेशक/प्रभारी(हिन्दी विभाग) ने अतिथि वक्ता एवं कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया।

द्वितीय सत्र का आयोजन मुख्यालय के ढेबरभाई सभाकक्ष में किया गया, जिसमें मुख्यालय में पदस्थ निदेशकों, उप निदेशकों एवं सहायक निदेशकों-१ ने भाग लिया। इस सत्र के अतिथि वक्ता श्री विश्वनाथ झा, उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार का परिचय सहायक निदेशक/प्रभारी (हिन्दी विभाग) ने दिया। श्री वाई.के.बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने श्री झा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपस्थित सभी निदेशकों, उप निदेशकों एवं सहायक निदेशकों-१ को कार्यालयीन कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी के प्रयोग पर ज़ोर दिया। द्वितीय सत्र का विषय "कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति और उसका अनुपालन" था। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अतिथि वक्ता ने बहुत ही सरल एवं सहज उत्तर दिये। अंत में श्री मिलिंद वाकोड़े, निदेशक, वन आधारित उद्योग ने अतिथि वक्ता एवं उपस्थित कर्मचारियों का धन्यवाद देकर आभार प्रकट किया।

☆☆

चंपारण : महात्मा का उदय

भारत की जंगे-आजादी के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह को मील का पत्थर माना जाता है। इसी आंदोलन की वजह से देशवासियों ने मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' के तौर पर पहचाना। गांधीजी ने यहीं से अहिंसा को एक कामयाब विचार के रूप में रोपा।

वैसे तो इतिहास की हर घटना की शताब्दी आती है और उसे सौ साल पुराना बना कर चली जाती है। हम भी इतिहास को बीते समय और गुजरे लोगों का दस्तावेज भर मानते हैं। लेकिन इतिहास बीतता नहीं है, नए रूप और संदर्भ में बार-बार लौटता है और हमें मजबूर करता है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने परिवेश को पहचानें! इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं कि वे जब भी आपको या आप उनको छूते-खोलते हैं तो आपको कुछ नया बना कर जाते हैं। इसे पारस-स्पर्श कहते हैं। इतिहास का पारस-स्पर्श! चंपारण का गांधी-अध्याय ऐसा ही पारस है! इस पारस के स्पर्श से ही गांधी को वह मिला और वे वह बने जिसकी खोज थी उन्हें, यानी इतिहास ने जिसके लिए उन्हें गढ़ा था। और वह गांधीजी का स्पर्श ही था कि जिसने अहिल्या जैसे पाषाणवत् चंपारण को धधकता शोला बना दिया था। यह सब क्या था और कैसे हुआ था?

15 अप्रैल,1917 को राजकुमार शुक्ल जैसे एक अनाम-से आदमी के साथ मोहनदास करमचंद गांधी नाम का आदमी चंपारण आया था। मोहनदास वर्षों बाद स्वदेश लौटे थे, चंपारण का नाम भी नहीं सुना था और नील की खेती के बारे में न के बराबर जानते थे। कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड से जो विदेश-यात्रा शुरू हुई थी वही उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गई और फिर वहीं अवस्थित भी कर आई थी सपरिवार! सब कुछ ठीकठाक ही चल रहा था। वकालत भी जम गई थी कि मॉरित्सबर्ग स्टेशन पर उस मूढ़मति टिकटचेकर ने उन्हें डिब्बे से उतार फेंकने का कारनामा कर डाला। अगर उस टिकट चेकर को जरा भी इल्म होता कि इस काले को डब्बे से उठा फेंकने से गोरों के साम्राज्य की नींव ही उखड़ जाएगी तो वह ऐसा कभी न करता! लेकिन उसने बैरिस्टर एम.के.गांधी को भीतर से मोहनदास करमचंद गांधी कर दिया जो धीरे-धीरे चोला उतारता-उतारता कब महात्मा गांधी और फिर बापू बन गया, इसकी खोज में आज भी इतिहास भटक ही रहा है! इसलिए यह याद रखने जैसा तथ्य है कि गांधीजी जब चंपारण गए तब तक वे एकदम परिपक्व सत्याग्रही बन चुके थे।

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का हथियार उन्हें

मिला, जिसे धारदार बना कर उन्होंने रंग और जातीय भेद के खिलाफ इस्तेमाल भी किया, अपने जीवन में भी और जीवन की दिशा में भी कितने फेर-फार किए। परिवार को अपनी तरह से जीने की दिशा में ढाला, अपने आश्रम बनाए, उसके अनुरूप जीने की पद्धतियां विकसित कीं, अपनी लड़ाई के पक्ष में जनमत बनाने के लिए इंग्लैंड तक की यात्रा की और विदेशी सरकार से लेकर विदेशी अखबार और विदेशी सामाज के लोगों तक को साथ लेने की कला विकसित की। जनरल स्मट्स के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत का वह नया रिश्ता बनाया जिसमें नागरिक और उसकी सरकार एक हैसियत पर आ सकती है। चंपारण आने से पहले गांधीजी युद्धभूमि में उतर चुके थे। जूलू विद्रोह के दौरान सार्जेंट मेजर एमके गांधी के नाम की पट्टी लगा कर भारतीयों की टुकड़ी के कमांडर बन कर वे युद्ध के मैदान में गोलियों के बीच भागते-दौड़ते घायल सिपाहियों की तिमारदारी कर चुकेथे। 'हिंद-स्वराज' नाम की कालजयी पुस्तिका लिख चुके थे। दक्षिण अफ्रीका का अपना संघर्ष जीत कर भारत आए तो रही-सही कसर गुरु गोखले ने पूरी कर दी। वचनबद्ध गांधीजी पूरे साल भर तक 'आंख खुली, मुंह बंद' कर सारा भारत घूमते रहे। देश देखा, लोग देखे, प्रकृति देखी और देखा हर मान-अपमान को सह कर जीने का भारतीय स्वभाव! इसी भारत-दर्शन के क्रम में वे यह पहचान सके कि सैकड़ों साल की गुलामी अब अवस्था नहीं, मन:स्थिति में बदल चुकी है।

राजकुमार शुक्ल गांधीजी को नील किसानों की दुरवस्था दिखाने के लिए चंपारण ले गए। गांधीजी ने यहां आ कर वह सब देखा जो गुलामी की बीमारी के विषाणु थे। यह जानना बड़ा मजेदार भी है और आंखें खोलने वाला भी कि वे यहां आकर अंग्रेजों से, निलहों से कोई लड़ाई लड़ते ही नहीं हैं। वे लड़ाई शुरू करते हैं गुलामी की मानसिकता से। वे रात-दिन गुलाम भारतीयों को उनकी गुलामी का अहसास कराते रहे। बिहार के पहले दर्जे के वकीलों की फौज उनके साथ आ जुटी। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर बाबू आदि सभी गांधी से सुरक्षित दूरी रख कर, गांधीजी के करीब आते गए। ये तब के वक्त में दस हजार रुपए तक की फीस वसूलने वाले वकील थे। गांधीजी ऐसी वकालत और ऐसी कमाई का संसार छोड़ कर ही आए थे तो इनकी चमक-दमक से अप्रभावित इन्हें समझाते थे कि लड़ाई न अधूरी होती है और न अधूरेमन से लड़ी जाती है। प्रोफेसर कृपलानी भी थे आसपास लेकिन वे गांधी को ताड़ने में ही अधिक लगे थे।

गांधीजी ने अपने मतलब के लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र आदि से बुलाया और सफाई से रहना, पढ़ना, खाना बनाना आदि शुरू करवाते हैं। सबसे पहले सबकी रसोई एक साथ, एक ही जगह से बने- वे इसका आग्रह करते हैं। हर बड़ा वकील अपने साथ सेवक, रसोइया ले कर आया होता है। गांधी धीरे से इसे अनावश्यक बताते हैं और समझाते हैं कि सब मिल कर एक-दूसरे की मदद से वे सारे काम कर सकते हैं जिनके लिए हम इन पर आश्रित हैं। वे कहते ही नहीं, बल्कि खुद ही करने भी लगते हैं। उस दिन तो हद ही हो गई जिस दिन दीनबंधु सीएफ एंड्रूज को (जो तब दीनबंधु नहीं कहलाते थे) मोतिहारी से बाहर जाना था और उनके लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं था। जैसे-तैसे रोटी और उबले आलू का खाना बना और एंड्रूज खाने बैठे तभी गांधीजी उन्हें देखने आ गए और यह देख कर पानी-पानी हो गए कि एंड्रूज एकदम कच्ची रोटी खा रहे थे, जो उनकी थाली में धर दी गई थी। गांधीजी लोगों पर नाराज हुए और फिर खुद ही रोटियां बनाने बैठे। वे रोटियां बेलत रहे, करीने से सेंकते रहे और कितने की मान-दुलार से एंड्रूज की थाली में डालते गए। बस, उस दिन से रसोई भी और नौकर भी एक हो गए। इन सबमें कहीं भी न अंग्रेज आते हैं और न उनसे लड़ाई आती है।

लेकिन गांधीजी के चंपारण पहुंचने से पहले ही उनकी कीर्ति वहां पहुंच चुकी थी। जनमानस में बनने वाली

छवि अहिंसक लड़ाई का बड़ा प्रभावी हथियार होती है। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी ने क्या किया, इसे न जानने वाले भी यह जान गए कि यह चमत्कारी आदमी है। रास्ते भर किसान ही नहीं, सरकारी अधिकारी भी गांधीजी को देखने आते रहते रहे। जितने लोग आते जाते, बातें उतने ही रंग की फैलती जातीं। अंग्रेज अधिकारी और प्रशासन हैरान था कि यह आदमी करना क्या चाहता है और यह जो करना चाहता है वह इसे करने दिया जाए तो पता नहीं यह क्या-क्या करने लग जाएगा! दक्षिण अफ्रीका में इनके आका इस आदमी के जाल में इसी तरह जा फंसे थे, वह कहानी गांधीजी के लोगों से ज्यादा अच्छी तरह सरकारी लोगों को पता थी।

15 अप्रैल को गांधीजी मोतिहारी पहुंचे और बाबू गोरख प्रसाद के घर पर उन्हें ठहराया गया। अंग्रेजों के बात-व्यवहार का गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका से अनुभव था। इसलिए वे तुरंत गिरफ्तारी की संभावना मान कर तैयार थे। उसी आधार पर सामान की गठरी बनी थी। सब जानना चाहते थे कि गांधीजी कल से सत्याग्रह कैसे शुरू करेंगे! गांधीजी एकदम ठंडे स्वर में बोले, 'कल मैं जसवलपट्टी गांव जाऊंगा!' सब एक-दूसरे से पूछते हैं-क्यों, वहां क्यों? पता चलता है कि वहां के एक प्रतिष्ठित गृहस्थ पर अत्याचार की ताजा खबर आई है! सब बड़े लोग कुछ परेशान हो जाते हैं। अत्याचार कहां नहीं है कि आप जसवलपट्टी जा रहे हैं! मोतिहारी मुख्य शहर है। यहां से आपको प्रचार मिलेगा न कि जसवलपट्टी से!

रात बीती। सुबह गांधीजी जसवलपट्टी जाने के लिए तैयार। धरणीधर बाबू और रामनवमी बाबू साथ निकले। सवारी मंगाई गई हाथी। जलता हुआ सूरज सिर पर है और गर्म हवा झुलसा रही थी। गांधीजी ने कभी हाथी की सवारी की नहीं थी और वह भी तीन आदमी एक साथ! लगभग टंगी हुई हालत में सफर शुरू। और गांधीजी की बात भी शुरू हुई। वे जब से मोतिहारी आए थे, यहां की महिलाओं की दशा उन्हें मथ रही थी। इसलिए इसकी ही चर्चा उन्होंने निकाली और कहा यह कि यह तो हमारी महिलाओं को मार ही देगा! अंग्रेज अधिकारी भी यही समझ रहे थे कि यह आदमी पता नहीं कब, कहां और कैसे हमें मार ही देगा और इसलिए बगैर कोई वक्त खोए वे ही आगे बढ़ कर गांधी से लड़ाई मोल लेते। रास्ते में हाथी से उतर कर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से उतर कर इक्का और इक्का से उतर कर टमटम की यात्रा करवाता है प्रशासन और फिर जिला छोड़ कर चले जाने का फरमान थमा देता है। 'मुझे इसका अंदेशा तो था ही!' कह कर गांधीजी चंपारण के जिलाधिकारी का आदेशपत्र लेते हैं। लिखा है, 'आपसे अशांति का खतरा है!' गांधीजी यह आदेश मानने से सीधे ही इनकार कर देते हैं। वे अपने साथियों में पहले से बना कर लाया वह हिदायतनामा बांट देते हैं जिसमें लिखा है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो किसे क्या करना है। यह सब तो अभूतपूर्व था!

अगले दिन, अगला नजारा कचहरी में खुला। बेतार से बात सारे चंपारण में फैल गई थी कि अब गांधीजी का चमत्कार होगा। कचहरी में किसानों का रेला उमड़ा पड़ा था! सरकारी वकील पूरी तैयारी से आया था कि इस विदेशपलट वकील को धूल चटा देगा! जज ने पूछा कि गांधी साहब आपका वकील कौन है, तो गांधीजी ने जवाब दिया

कोई भी नहीं! फिर ? गांधीजी बोले, ' मैंने जिलाधिकारी के नोटिस का जवाब भेज दिया है! अदालत में सन्नाटा खिंच गया! जज बोला, 'वह जवाब अदालत में पहुंचा नहीं है।' गांधीजी ने अपने जवाब का कागज निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। कचहरी में इतना सन्नाटा था कि गांधीजी के हाथ की सरसरहाट तक सुनाई दे रही थी।

और उन्होंने कहा कि अपने देश में कहीं भी आने-जाने और काम करने की आजादी पर वे किसी की, कैसी भी बंदिश कबूल नहीं करेंगे। हां, जिलाधिकारी के ऐसे आदेश को न मानने का अपराध मैं स्वीकार करता हूं और उसके लिए सजा की मांग भी करता हूं। गांधीजी का लिखा जवाब पूरा हुआ और इस खेमे में और उस खेमे में सारा कुछ उलट-पुलट गया। न्यायालय ने ऐसा अपराधी नहीं देखा था जो बचने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। देशी-विदेशी सारे वकीलों के लिए यह हैरतअंगेज था कि यह आदमी अपने लिए सजा की मांग कर रहा है जबकि कानूनी आधार पर सजा का कोई मामला बनता ही नहीं है। सरकार, प्रशासन सभी अपने ही बुनेजाल में उलझते जा रहे थे। जज ने कहा कि जमानत ले लो तो जवाब मिला, 'मेरे पास जमानत भरने के पैसे नहीं हैं!' जज ने फिर कहा कि बस इतना कह दो कि तुम जिला छोड़ दोगे और फिर यहां नहीं आओगे तो हम मुकदमा बंद कर देंगे। गांधीजी ने कहा, 'यह कैसे हो सकता है! आपने जेल दी तो उससे छूटने के बाद मैं स्थाई रूप से यही चंपारण में अपना घर बना लूंगा।' यह सब चला और फिर कहीं दिल्ली से निर्देश आया कि इस आदमी से उलझो मत, मामले को आगे मत बढ़ाओ और गांधी को अपना काम करने दो। बस, यही सरकारी आदेश वह कुंजी बन गई, जिससे सत्याग्रह का ताला खुलता है। ताला क्या खुलता है सारे वकील, प्रोफेसर, युवा, किसान-मजदूर सब खिंचते चले आए और जितने करीब आए, उतने ही बदले।

गांधीजी सबसे वादा भी ले लेते हैं कि जेल जाने की घड़ी आएगी तो कोई पीछे नहीं हटेगा। इन नामी वकीलों ने अब तक दूसरों को जेल भिजवाने का या जेल जाने से बचाने का ही काम किया था, खुद जेल जाने की तो कल्पना भी नहीं की थी। जेल जाना बदनामी की बात भी थी। गांधी सबको समझा रहे थे कि सच की लड़ाई में जेल जाना सम्मान की ही बात नहीं है बल्कि जरूरी बात भी है। और जब वे यह कह रहे थो तो सभी जानते थे वे खुद दक्षिण अफ्रीका की जेलों में रह कर और जीत कर आए हैं।

किसानों से बयान दर्ज करवाने का काम किसी युद्ध की तैयारी जैसा चला। देश भर से आए विभिन्न भाषाओं के लोग, बिहार के लोगों की मदद से बयान दर्ज करने के काम में जुटे। गांधी जैसे एक वकालतखाना ही चला रहे हों। तथ्यों का सच्चा और संपूर्ण आकलन कैसे एक अकाट्य हथियार बन गया-'डेटा कलेक्शन' की आज की पेशेवर दुनिया में चंपारण इसका पदार्थ-पाठ बन सकता है।

गांधीजी यह भी पहचान गए कि नील की खेती के पीछे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां तो हैं ही, नकदी फसल का किसानों का आकर्षण भी है। इस लोभ में वे अपनी कृषि-प्रकृति के खिलाफ जा कर काम करने को तैयार हुए। आज खेती का सबसे बड़ा संकट यह है कि हमने इसे प्रकृति के साथ रासायनिक युद्ध में बदल दिया है जबकि खेती है तो शरीर-विज्ञान ! चंपारण सत्याग्रह का यह पहलू बहुत उभरा नहीं क्योंकि मैदान में लड़ाई कुछ और ही चल रही थी। लेकिन चंपारण के काम की दिशा का जब विस्तार हुआ और गांधी का सत्याग्रह पूरी तरह खिला तब गांधी इन सारे सवालों को छूने में कामयाब हुए।

आज हमारी खेती-किसानी जब लाचारी और आत्महत्या का दूसरा नाम बन गई है, हमें चंपारण सत्याग्रह की इस दिशा का ध्यान करना चाहिए। गांधी और चंपारण दोनों ही आज के हिंदुस्तान की दशा सुधारने और दिशा दिखाने का काम एक साथ कर सकते हैं। शर्त इतनी ही है कि हम दशा सुधारने और दिशा खोजने के बारे में ईमानदार तो हों।

सफल सत्याग्रह

मोहनदास करमचंद गांधी ने 1917 में संचालित चंपारण सत्याग्रह न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती दी थी। वे दस अप्रैल, 1917 को जब बिहार आए तो उनका एक मात्र मकसद चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझना, उसका निदान और नील के धब्बों को मिटाना था। एक स्थानीय पीड़ित किसान राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (1916) में अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती कराई जाने के संदर्भ में शिकायत की थी। शुक्ल का आग्रह था कि गांधीजी इस

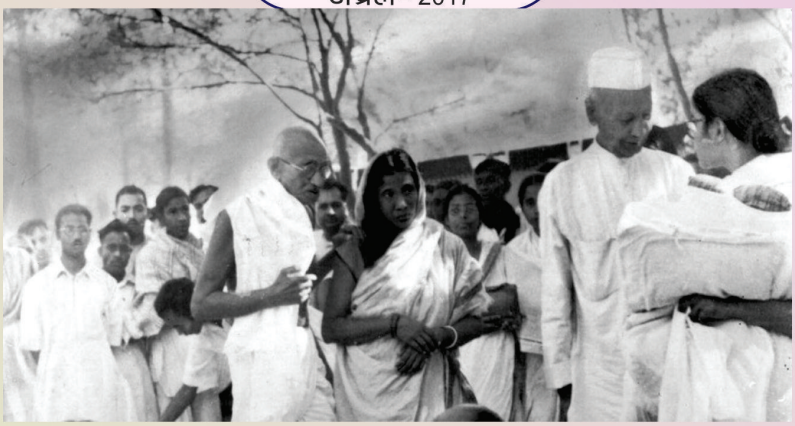

आंदोलन का नेतृत्व करें। गांधीजी ने इस समस्या को न सिर्फ गंभीरतापूर्वक समझा, बल्कि इस दिशा में आगे बढ़े।

गांधी ने 15 अप्रैल, 1917 को मोतिहारी पहुंचकर 2900 गांवों के तेरह हजार किसानों की स्थिति का जायजा लिया। 1916 में लगभग 21,900 एकड़ जमीन पर आसामीवार, जिरात, तीनकठिया आदि प्रथा लागू थी। चंपारण के किसानों से मड़वन, फगुआही, दषहरी, सट्टा, सिंगराहट, धोड़ावन, लटियावन, शरहवेशी, दस्तूरी, तवान, खुश्की समेत करीब छियालीस प्रकार के 'अवैध कर' वसूले जाते थे। कर वसूली की विधि भी बर्बर और अमानवीय थी। नील की खेती से भूमि बंजर होने का एक अलग भय था।

निलहों के विरुद्ध राजकुमार शुक्ल 1914 से ही आंदोलन चला रहे थे। लेकिन 1917 में गांधीजी के सशक्त हस्तक्षेप ने इसे व्यापक जन आंदोलन बनाया। आंदोलन की अनूठी प्रवृत्ति के कारण इसे राष्ट्रीय बनाने में गांधीजी सफल रहे। 1867 में पंडौल का नील आंदोलन क्षेत्रीय था, जबकि 1908 का आंदोलन राज्य स्तरीय। गांधी के संगठित नेतृत्व ने चंपारण के किसानों के भीतर जबर्दस्त आत्मविष्वास और सफलता का संचार किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी के इस पहल को विफल बनाने के लिए धारा-144 के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने का नोटिस भी भेजा। लेकिन गांधीजी इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। गांधीजी के शांतिपूर्ण प्रयास का अनुचित ढंग से दमन करना ब्रिटिष सरकार के लिए भी कठिन सिद्ध हो रहा था। उधर, गांधीजी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली जा रही थी। तत्कालीन समाचार पत्रों ने चंपारण में गांधीजी की सफलता को काफी प्रमुखता से प्रकाशित किया। निलहे बौखला उठे। गांधीजी को फंसाने के लिए तुरकौलिया के ओल्हा फैक्टरी में आग लगा दी गई। लेकिन गांधीजी इससे प्रभावित नहीं हुए।

बाध्यता के कारण बिहार के तत्कालीन डिप्टी गर्वनर एडवर्ड गेट ने गांधीजी को वार्ता के लिए बुलाया। किसानों की समस्याओं की जांच के लिए 'चंपारण एग्रेरियन कमेटी' बनाई गई। सरकार ने गांधीजी को भी इस समिति का सदस्य बनाया। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तीनकठिया व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई। किसानों के लगान में कमी लाई गई और उन्हें क्षतिपूर्ति का धन भी मिला। हालांकि, किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए ये उपाय काफी न थे। फिर भी पहली बार शांतिपूर्ण जनविरोध के माध्यम से सरकार को सीमित मांगों को स्वीकार करने पर सहमत कर लेना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी। सत्याग्रह का भारत के राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयोग इस लिहाज से काफी सफल रहा। इसके बाद नील की खेती जमींदारों के लिए लाभदायक नहीं रही और शीघ्र ही चंपारण से नील कोठियों के मालिकों का पलायन प्रारंभ हो गया।

इस आंदोलन का दूरगामी लाभ यह हुआ कि इस क्षेत्र में विकास की प्रारंभिक पहल हुई, जिसके तहत कई पाठशाला, चिकित्सालय, खादी संस्था और आश्रम स्थापित किए गए। इस आंदोलन का एक अन्य लाभ यह भी हुआ कि चंपारण से ही मोहनदास करमचंद गांधी का 'महात्मा' बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ आमजनों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सहज हथियार (सत्याग्रह) मिला। चंपारण सत्याग्रह को आज के संदर्भ में देखना चाहिए। देश के किसान आत्महत्या के लिए विवश हैं। नई आर्थिक नीति के प्रभाव से आर्थिक विषमता बढ़ी है। तथाकथित सामाजिक न्याय के नाम पर जातिगत विद्वेष लगातार बढ़ रहा है और राजनीति में वंषवाद पुख्ता होता चला जा रहा है। महात्मा गांधी के संदेश-सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाषयता आदि को लोग नजर अंदाज कर रहे हैं। इस दिशा में राज्य और केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को पहल करने की आवश्यकता है।

(राम कुमार निराला)

– कुमार प्रशांत,साभारः जनसत्ता, 22 मई, 2016

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....

KVIC bags largest bulk order for khadi

The order for 98,000 metres of fabric is valued at ₹2 crore

New Delhi: The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has received its largest bulk order for supply of 98,000 metres of khadi fabric to Raymond Ltd.

Confirming the order, valued at over Rs 2 crore, KVIC Chairman V K Saxena said it is the largest ever the commission has received from any corporate.

He said KVIC is heralding the entry of corporate and private sector giants into the marketing of khadi fabric, thus providing sustainable employment and livelihood support to the artisans.

KVIC had signed an agreement with Raymond in December last year. After joint visits, Raymond selected various clusters in Gujarat, Rajasthan and other places for procurement of the fabric.

KVIC will supply grey and finished khadi fabric to Raymond as per their requirements.

Raymond will provide design input and undertake value addition to the fabric to create designer wear for the high-end market.

Saxena said KVIC is focused on the welfare of khadi artisans, and so 5 per cent out of the margin of these special supplies will be provided as additional wage support to the artisans involved in these clusters. He added that the bulk order will generate an additional 3,92,000 man hours for the khadi artisans. -PTI

Bharat Satya

L- Swami Vivekananda | Stop Rape

Raymond to buy 98,000 metres khadi fabric from KVIC

Mumbai : Khadi and Village Industries Commission (KVIC) received its largest bulk order yesterday for the supply of 98000 meters Khadi fabric to Raymond Ltd in which 32000meters will be supplied before 31st March and rest quantity by May end. Order values more than Rs. 2 crores . Confirming the receipt of the order KVIC Chairman VK Saxena said it is largest ever order received by KVIC from any corporate giant. He said Khadi heralding the entry of Corporate and private sector giants into marketing of Khadi fabric and thus providing sustainable employment and livelihood support to the artisans. KVIC had signed an agreement with Raymond on 06.12.2016 and as a part of this convergence the initial order for Khadi fabric has been placed by Raymond Ltd said CEO Raymonds Sanjay Behl . Earlier during January and February Raymond took more than 6000 Mtrs fabric of different varieties from KVIC for testing and sampleing.

After joint visits, Raymond has selcted various clusters from Gujarat,Rajasthan and other places to procure fabric. KVIC will supply grey and finished Khadi fabric to Raymond as per their requirements. Raymond will provide design input and undertake value addition to the Khadi fabric to create designer wear for the high end market. Saxena informed that the focus of KVIC is the welfare of the Khadi artisans and therefore 5% out of the margin of these special supplies will be provided as additional wage support to the Khadi artisans involved in these clusters . He further added that this bulk order will generate an additional 3,92,000 man hours to the Khadi artisans. As per agreement Raymond will procure minimum worth Rs 2.50 cr fabric per year.

Raymond to buy Khadi fabric from KVIC

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Top fashion retailer Raymond Ltd has asked Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to supply 98,000 meters of Khadi fabric, out of which 32,000 meters will be supplied before 31 March and the rest by May-end. The order values over Rs 2 crore.

Confirming the receipt of the order, KVIC Chairman VK Saxena said it is the largest-ever order received by KVIC from a top brand. He also said that this move would herald the entry of corporate sector into marketing of Khadi fabric.

KVIC had signed an agreement with Raymond in December 2016 and as a part of this convergence, the initial order for Khadi fabric has been placed by Raymond Ltd, said CEO Raymonds Sanjay Behl. Earlier during January and February, Raymond took more than 6,000 meters of different varieties from KVIC for testing and sampleing.

After joint visits, Raymond has selcted various clusters in Gujarat, Rajasthan and other states to procure the fabric. KVIC will supply grey and finished Khadi fabric to Raymond as per its requirements. Raymond will provide design input and undertake value addition to the Khadi fabric to create designer wear for the high-end market.

Saxena informed that the focus of KVIC is the welfare of the Khadi artisans and therefore, 5 per cent out of the margin of these special supplies will be provided as additional wage support to the Khadi artisans involved in these clusters. He further added that this bulk order will generate an additional 3,92,000 man-hours to the Khadi artisans.

As per agreement, Raymond will procure fabric worth a minimum Rs 2.50 cr per year from KVIC. PTI

Giving khadi the required makeover

ANCELA JAMINDAR

Khadi Village and Industries Commission's (KVIC) 642nd monthly standing finance committee meeting was held at Sabarmati Ashram on Monday — a first in the 60-year history of KVIC. In the meeting inside the Ashram, KVIC members sat on the floor, keeping Gandhian values in mind.

The commission took three important decisions in the meeting which included rise in wages of khadi artisans from Rs 5.50 per hank to Rs 7. Rise will help more than 3.5 lakh people across India to earn around Rs 200 a day. Wage hike will be in effect from April 1, 2017. KVIC also decided to allow khadi stores to sell products made in jails and revival of khadi institutions which are in poor state across the country. After the meeting, KVIC chief VK Saxena visited an exhibition put together by the state unit of the commission. (Above) Gujarat State director Sanjay Hedaoo (L) was seen taking Saxena through the exhibition.

रेमंड को बेचा 98000 मीटर खादी वस्त्र

केवीआईसी को मिला सबसे बड़ा ऑर्डर

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को कॉरपोरेट कंपनी से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है. केवीआईसी को रेमंड लिमिटेड से 98000 मीटर खादी कपड़ों की एक मुश्त आपूर्ति के आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमे से 32000 मीटर खादी कपड़े की आपूर्ति 31 मार्च से पहले कर दी जायेगी एवं शेष आपूर्ति मई के अंत तक की जायेगी.

खादी वस्त्रों की बिक्री में आएगी और तेजी

केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि किसी भी कॉरपोरेट कंपनी द्वारा आयोग को दिया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑर्डर है. खादी वस्त्रों की मार्केटिंग में कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है. इससे खादी वस्त्रों की बिक्री में और तेजी आएगी. रेमंड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बहल ने कहा कि केवीआईसी ने 6 दिसंबर, 2016 को रेमंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और इस समझौते के अंतर्गत रेमंड के द्वारा खादी वस्त्र का यह शुरूआती आपूर्ति आदेश दिया गया है. रेमंड ने गुजरात, राजस्थान और अन्य स्थानों से कपड़े तैयार करने के लिए विभिन्न क्लस्टरों का चयन किया है. केवीआईसी रेमंड को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ग्रे और पूर्ण निर्मित खादी कपड़े की आपूर्ति करेगा.

कारीगरों के कल्याण पर ध्यान

सक्सेना ने कहा कि कारीगरों के कल्याण पर ही आयोग का पूरा ध्यान केंद्रित है इसलिए इन क्लस्टरों में कार्यरत खादी कारीगरों को इस तरह की विशेष आपूर्ति के मार्जिन से 5 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह थोक आदेश खादी कारीगरों के श्रम में 3,92,000 अतिरिक्त मानव श्रम घंटों का निर्माण करेगा. केवीआईसी और आयोग के बीच हुए समझौते के अनुसार रेमंड प्रति वर्ष न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपए मूल्य के वस्त्र आयोग से क्रय करेगा.

खादी ग्रामोद्योग में ई- गवर्नेंस

नए युग की हुई शुरुआत

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने काम में पारदर्शिता तथा योजनाबध्द दक्षता लाने के लिए अटोस इंडिया के माध्यम से ई-गवर्नेंस की शुरुआत की . केवीआईसी के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना ने आयोग के केंद्रीय कार्यालय में ई- गवर्नेंस की शुरुआत की. सक्सेना के अनुसार अटोस इंडिया की भागीदारी के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और डिजिटाइजेशन का उन्नयन करने की एक बड़ी पहल है. इससे पूरे भारत में केवीआईसी के एक नए युग की शुरूआत होगी.

डिजिटाइजेशन कार्य की यह व्यवस्था आयोग के सभी कार्यालयों, बिक्री केन्द्रों, पूनी संयत्रों, उत्पादन केन्द्रों इत्यादि में एकीकृत रूप से की जा रही है. उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस की शुरुआत व्यवस्था की संरचना, योजना बनाने, बजट बनाने, व्यय प्रबंधन करने, उत्पादन करने और खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री आदि क्षेत्रों से संबंधी कार्य में तीव्रता लाने के लिए की गई है.

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

ई- गवर्नेंस प्रोजेक्ट को, खादी सुधार विकास कार्यक्रम (के.आर.डी.पी.) के तहत निधियन किया गया है इसका कार्यान्वयन आयोग के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय सहित 6 केंद्रीय पूनी सयंत्रों, 44 राज्य तथा मंडलीय कार्यालयों, सभी बिक्री केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, आदि की सभी वित्तीय गतिविधियों को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में किया जायेगा.

Khadi India

स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056 वेबसाईट : www.kvic.org.in

भारत में हम रोजगार सृजन करते हैं तथा समृद्धि बुनते हैं